areas of Gujarat and Maharashtra has not been undertaken inspite of Government policies;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the details of those districts of Gujarat and Maharashtra where no Government or private industry has been set up; and

(d) what are the details of measures being contemplated by Government to set up industries and provide employment to the rural and tribal unemployment in those districts ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) and (b) The responsibility of Industrial Development lies primarily with the State Governments who offer various incentives and schemes. However, with a view to ensuring development of backward areas, the Government of India is also implementing various schemes whose details are in Annexure [*See* Appendix 172, Annexure 62].

(c) The district-wise information in respect of IEMs field in the States of Gujarat and Maharashtra is as at Annexure. [*See* Appendix 172, Annexure 63].

(d) Same as (a) and (b).

मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में उद्योग संवर्धन हेतु समिति का गठन

2616. **श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग लगाने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई समिति गठित की है ;

(ख) सरकार द्वारा इस क्षेत्र के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति लाने और वहां के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं ; और

(ग) सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में इस योजना के लिए कितनी राशि आबंटित की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व है ताकि उद्योग ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में आ सकें । शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु प्रधान मंत्री रोजगार योजना देश भर में कार्यान्वित की जा रही है । इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन और रोजगार सृजन के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग भी अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष (1994-95) के बजट में पूरे देश के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना हेतु 145 करोड़ रूपये और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं के लिए 214 करोड़ रुपये की राशि आबंटन किया गया है ।

Investments by Foreign Institutional Investors

2617. SHRI SANJAY DALMIA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state the total investments made by Foreign Institutional Investors in the Indian Capital Market so far ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI) : As per the reports filed by the Custodians for Foreign Institutional Investors (FIIs) registered with Securities and Exchange Board of India (SEBI), as on 31-10-94, the cumulative net investments under Portfolio investment scheme for Foreign Institutional Investors has been Rs. 9022.20 crores.

Amendment of Indian Patents Act in fulfilment of GATT

2618. SHRI SANJAY DALMIA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have decided to appropriately amend Indian Patents Act in fulfilment of the GATT agreement;

(b) the key areas which require amendments in the Indian Patents Act;